



चित्र 10.1 लाइफ पत्रिका से लिया गया चित्र:

(अ) मालगाड़ी से अन्न जमा करने का प्रयास करते हुए बच्चे (आ) भूमि पर गिरे हुए अन्न को बुहारती हुई महिला

आज़ादी से पहले भारत में अकाल में खाद्य का बृहद स्तर पर अभाव था। बड़े स्तर पर भूख से मौत एक सामान्य कारण था। उदाहरण के लिए 1943-45 में बंगाल में अकाल के समय 3 से 5 मिलियन लोग बंगाल, असम और उड़ीसा के आस-पास रहते थे। निम्नलिखित को पढ़िए।

“मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। जीवनयापन के लिए मैं प्रतिदिन एक मज़दूर का कार्य करता था। उस समय अपने पिताजी को गाँव में छोड़कर, अपने भाई-बहनों को साथ लेकर कलकत्ता आ गया। भोजन के लिए उनके पास केवल थोड़ा सा आटा था। हम जहाँ भी भोजन बाँटा जा रहा था उन सभी जगहों पर गये। कलकत्ता की गलियों में मैंने बहुत से लोगों को संघर्ष करते हुए देखा। मैंने उन माताओं को देखा जिनके बेटे वास्तव में मर चुके थे, पर उन्हें हाथों में थामे वे घूम रही थीं। लेकिन माताएँ फिर भी उन पर पानी के छींटे मार रही थी ताकि, वे सक्रिय अवस्था में आ सकें। मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा। उन लोगों को देखा जो साँप और घास तक को खा रहे थे। मैं अपने एक भाई-बहन को खो चुका था।

वहाँ पर कुछ लोग किसान थे जो कृषि से जुड़े थे। वे भिखारी नहीं थे इसलिए भीख माँगना नहीं जानते थे। उनके अंदर बहुत स्वाभिमान था। जब वे आये तो फुटपाथ पर बैठे-बैठे उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी तस्वीरें जब कलकत्ता की जनता के सामने आईं तभी वे लोग इतने बड़े स्तर की आपदा के बारे में समझ सके।”

बंगाल में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण के आयोजन को ठुकराने के कारण भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही बंगाल में महान् अकाल पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों ने लोगों में खाद्यान्न की सुनिश्चितता के लिए

अनेक प्रणालियों का निर्माण किया। राशन की दुकान जहाँ जाकर जनता सब्सिडी मूल्य (अनुदान) पर खाद्य पदार्थ खरीदती हैं। मध्याह्न भोजन जिसे आप जैसे बहुत से लोग खाते हैं। आंगनबाड़ी जहाँ छोटी आयु के बच्चे सुरक्षा पाते हैं, दिन का भोजन आदि के लिए सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस अध्याय में हम खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों को देखेंगे।

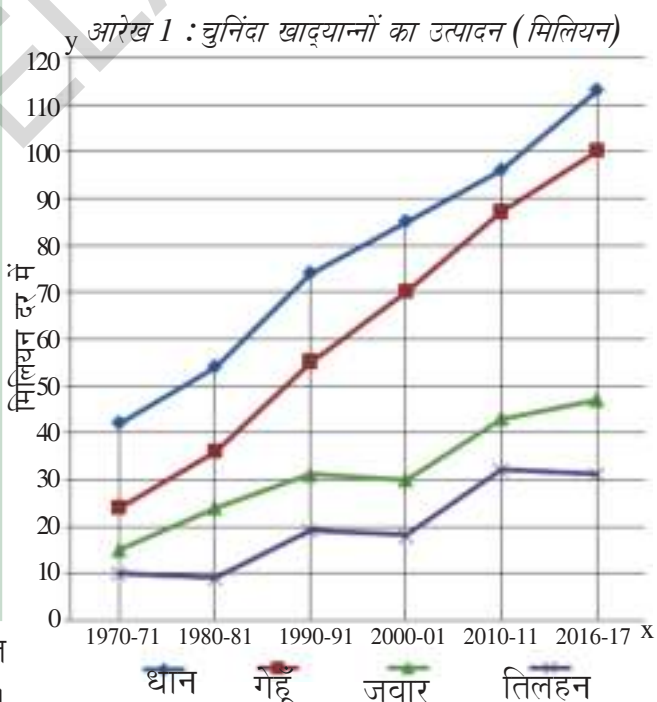
पहला खण्ड संपूर्ण खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देता है। उत्पादन का मुद्दा और भोजन की उपलब्धता सारे देश के लिए है। दूसरा खण्ड जनता को मिलने वाली सुलभताओं के बारे में चर्चा करता है - उपलब्ध भोजन लोगों तक पहुँचे-इसे कोई एक व्यक्ति कैसे सुनिश्चित कर सकता है। अंत में, इन नीतियों की प्रभावोत्पादकता को जानने के लिए हमें परिवारों के पोषण स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

## देश के लिए खाद्य सुरक्षा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि (Food Security for the Country, Increasing foodgrain production)

खाद्य सुरक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में उनका उत्पादन करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत में इसका अभिप्राय है कि, सरकार इस तरह की स्थितियों को बनाए ताकि किसान प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन कर पाए।

आरेख 1 का निरीक्षण करें एवं रिक्त तालिका को भरें। (प्रत्येक बिंदु का महत्व और y-अक्ष की सही राशि को जानने के लिए एक स्केल का उपयोग करें।)

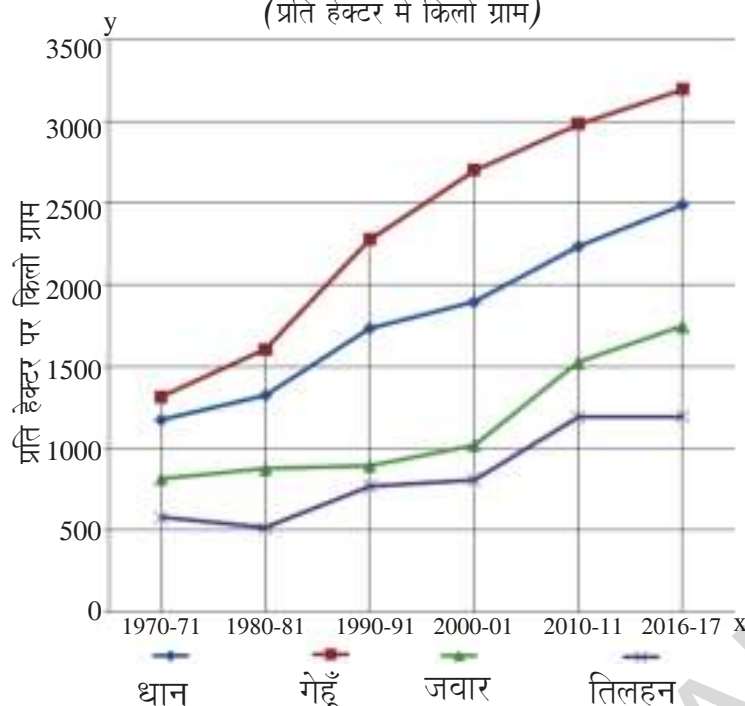
- खाद्य उत्पादन में 1970-71 से ..... तक वृद्धि हुई। धान के उत्पादन में, 1970-71 में 40 मिलियन टन से 2010-11 तक ..... मिलियन टन की वृद्धि हुई है। गत 40 वर्षों में उत्पादन में वृद्धि की एक और प्रमुख खाद्य फ़सल .....। धान, गेहूँ की तुलना में - 1970-211 तक के समय में ..... उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण ..... हो सकता है।
- अध्याय '9' 'रामपुर गाँव : एक ग्रामीण - अर्थ व्यवस्था' में भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन वाले भाग को फिर से पढ़िए। भूमि से फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए कौन-कौन से संभावित कारक है?



पिछले कुछ दशकों से खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। फसल एक जटिल चरराशि बन गयी है। आरेख:2 को देखिए।

प्रति हेक्टर फसल की उपज में आवश्यक आगंतों द्वारा उचित तरीके उपलब्ध कराकर फसल में न्याय संगत तरीके से वृद्धि की जा सकती है। इसका एक रास्ता यह है कि, सिंचाई के जल का उपयोग समुचित तरीके से हो।

आरेख 2 : चुनिंदा खाद्यान्नों की फसल  
(प्रति हेक्टर में किलो ग्राम)



क्योंकि जल सिंचाई का एक आवश्यक साधन है, इसलिए इसे प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कम उपज वाली पैदावार को सारणी 2 में दिखाया गया है जो कि ज्यादातर सूखी जमीन में पैदा होती हैं। जहाँ वर्तमान में यहाँ तक कि, भविष्य में भी सिंचाई की सुविधा कम है। सूखा अवरोधक फसलों को स्थानीय स्थिति में भी लगाने पर पैदावार में वृद्धि हो सकती है।

यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करें कि, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन इस प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त न हो। कुछ वैज्ञानिक एवं कुछ लोग जो कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं, वे बताते हैं कि किस प्रक्रिया द्वारा भारत में धान

और गेहूँ के खेतों की जुताई होती है। किस तरह अवैज्ञानिक तरीके से रासायनिक खाद कीटनाशक का लगातार प्रयोग होता है। जो उपज की दर में निरंतर किंतु अस्थायी वृद्धि करता है। यह विधि नम भूमि के अपक्षय को बढ़ाती है। यदि यही स्थिति रहेगी तो वृद्धि की अपेक्षा हमारी फसलों और कम होती जायेगी एवं भूमिगत जल में भी कम होगी।

नीचे के गद्यांश में धान और गेहूँ की प्रति हेक्टर उपज का वर्णन किया गया है। रिक्त स्थान भरिए।

- दो फसलों ----- और ----- में हमेशा न्यून पैदावार होती है जब हम धान और गेहूँ से उसकी तुलना करते हैं। कुछ वर्षों से दोनों में धीमी वृद्धि है।
- जवार की पैदावार की वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? चर्चा कीजिए।
- लंबे समय से धान और गेहूँ की पैदावार में वृद्धि में योगदान देने वाले कारक क्या है?

### खाद्यान्नों की उपलब्धता (Availability of Foodgrains)

हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि एक देश संपूर्ण देश खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ है या नहीं। हम कैसे समझेंगे कि, सभी के लिए भोजन है या नहीं? क्या वह भोजन परिवार तक पहुँचता है? इसकी जाँच बाद में की जाएगी। पहले हम यह देखें कि क्या उपलब्ध है? अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगी एवं कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि होगी। खाद्यान्न में वृद्धि क्या सच में संभव है?

यहाँ उत्पादन एवं खाद्यान्न की उपलब्धता में अंतर है? इसका आकलन ऐसे हो सकता है।

**खाद्यान्न की वार्षिक उपलब्धता** = उस वर्ष के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन (उत्पादन-बीज, भोजन, व्यर्थपदार्थ) + वास्तविक आयात (आयात - निर्यात) - स्टॉक में परिवर्तन सरकार के साथ (वर्ष के अंत में स्टॉक - प्रारंभ में स्टॉक)

**प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता** = (वर्ष भर के खाद्यान्न की उपलब्धता ÷ आबादी)/365

उत्पादन निर्यात और सरकारी स्टॉक में परिवर्तन संबंधी सूचनाएँ नीचे तालिका में दी गयी हैं। (1971, 1999 एवं 2011 के) उत्पाद, आयात का एक तरीका है जिससे खाद्यान्न की उपलब्धि किसी विशेष साल में बढ़ाई जा सकती है। सरकार के भंडार में बदलाव खाद्यान्न की उपलब्धि बढ़ाने का एक और तरीका है। उदाहरण के लिए सरकार अपने भंडार में से चावल बेचकर उसकी उपलब्धि बढ़ा सकती है।

जिस समय सरकार का चावल भंडार कम होता है, उसी समय उस साल उपलब्ध चावल की मात्रा खपत के लिए बढ़ जाती है।

(सरकारी भंडार के बारे में आप अगले भाग में पढ़ेंगे।)

जैसा कि 1971 के लिए दिखाया गया है, वैसे ही 1991 और 2011 के प्रति व्यक्ति के लिए खाद्यान्न उपलब्धि की गणना की जाए।

**तालिका 1: खाद्यान्न की उपलब्धि - प्रति व्यक्ति**

| वर्ष    | जनसंख्या (मिलियन) | खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन | वास्तविक निर्यात | सरकारी भंडार में परिवर्तन | खाद्यान्न की वास्तविक उपलब्धता     | प्रति दिन प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध (ग्राम)                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| col (1) | col (2)           | col (3)                       | col (4)          | col (5)                   | col (6)                            | col (7)                                                                                                                                                                                             |
| 1971    | 551               | 94.9                          | 2                | 2.6                       | col (3) + col (4) - col (5) = 94.3 | $= \{ \text{col (6)} / \text{col (2)} \} / 365$ $= (94.3 / 551) / 365$ $= 0.000469 \text{ टन} *$ $= 0.000469 \times 1000$ $= 0.469 \text{ किलोग्राम} *$ $= 0.469 \times 1000$ $= 469 \text{ ग्राम}$ |
| 1991    | 852               | 154.3                         | -0.1             | -4.4                      |                                    |                                                                                                                                                                                                     |
| 2011    | 1202              | 214.2                         | -2.9             | 8.2                       |                                    |                                                                                                                                                                                                     |

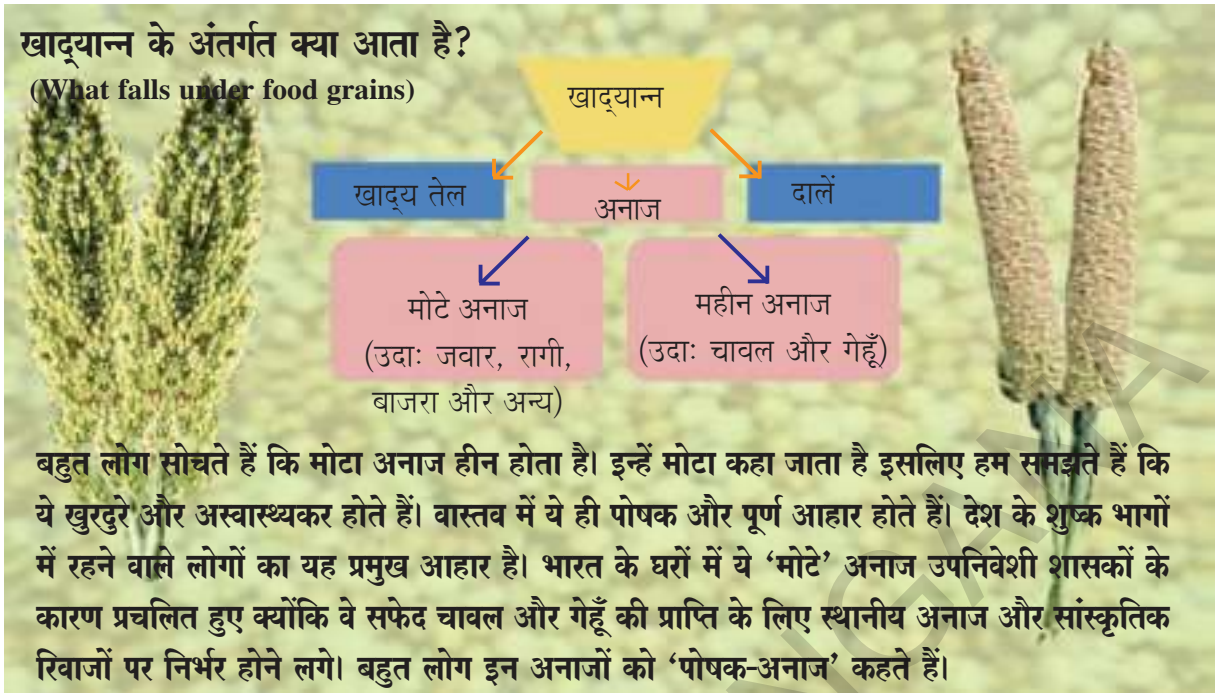
\* नोट: 1 टन = 1000 किलोग्राम; 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम

# मिलियन टन

- अपनी गणना के आधार पर रिक्त स्थान भरिए: 1971 और 1991 के बीच प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि \_\_\_\_\_ (बढ़ी/घटी) है लेकिन 2011 में \_\_\_\_\_ (कम/ज्यादा) थी। कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि कम होने के बावजूद यह सब हुआ है। भविष्य में सरकार को \_\_\_\_\_ के जरिए अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करनी होगी।

## खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आता है?

(What falls under food grains)



बहुत लोग सोचते हैं कि मोटा अनाज हीन होता है। इन्हें मोटा कहा जाता है इसलिए हम समझते हैं कि ये खुरदुरे और अस्वास्थ्यकर होते हैं। वास्तव में ये ही पोषक और पूर्ण आहार होते हैं। देश के शुष्क भागों में रहने वाले लोगों का यह प्रमुख आहार है। भारत के घरों में ये 'मोटे' अनाज उपनिवेशी शासकों के कारण प्रचलित हुए क्योंकि वे सफेद चावल और गेहूँ की प्राप्ति के लिए स्थानीय अनाज और सांस्कृतिक रिवाजों पर निर्भर होने लगे। बहुत लोग इन अनाजों को 'पोषक-अनाज' कहते हैं।

## अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता (Availability of Other Food Items)

जब लोग प्रचुर मात्रा में फल, सब्जी, दूध और माँस, मछली की माँग करते हैं तो यह उपभोगविधि में परिवर्तन लाता है। यह एक अच्छा संकेत है उपभोक्ता के लिए और उत्पादक के लिए। उपभोक्ताओं को विभिन्न खाद्य पदार्थों और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किसान विभिन्न प्रकार की फसल का उत्पादन कर रहे हैं ताकि खाद्यान्न में विविधता के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो। आप स्मरण कीजिए कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि, तेलंगाणा में किस तरह किसान तनाव की स्थिति से गुजरें हैं। यहाँ तक कि, उन्होंने आत्म हत्या भी की। क्योंकि पिछले दो दशकों में तेलंगाणा में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नगदी फसलों जैसे कपास को उगाया गया था। किसान इसके बदले में अपना ध्यान इसके समान अन्य कार्यों जैसे - पोल्ट्री, (मुर्गीपालन) मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि जो नए अवसर किसानों को देते हैं, उन पर लगा सकते हैं।

कुछ वर्षों में अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन यह खाद्य की आवश्यकता की न्यूनतम दर है। जो संतोषजनक नहीं है। आहार विज्ञानी यह सलाह देते हैं कि, प्रत्येक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम फल एक दिन में लेना चाहिए। किंतु यह खाद्य सामग्री क्रमशः 180 ग्राम एवं 58 ग्राम ही मिल पाती है। उसी तरह अंडा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति 180 है पर इसकी उपलब्धता है-30। मांस की आवश्यकता 11 किलो है पर प्रत्येक व्यक्ति को 3.2 किलोग्राम उपलब्ध हो पाता है। हमें 300 मिली लीटर दूध की आवश्यकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 210 मिलीलीटर दूध ही उपलब्ध हो पाता है।

किसानों को निवेश के संबंध में सहयोग की आवश्यकता है। अन्य विविध खाद्यान्न के लिए उन्हें बाज़ार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इस नयी परिस्थिति में जिस चुनौती का सामना वे 'बाज़ार' में करते हैं उसमें किसानों को समर्थन, सहयोग एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है।

## कृषिगत विविधता (Agricultural Diversification)

मिदनापुर में लाल लेटराइट मिट्टी है। यह गाँव बोर कोल्लाह ग्राम पंचायत क्षेत्र में कसपाल था। ज्यादातर लोगों के पास ट्यूबवेल थे। जल स्रोत में वृद्धि के लिए बैंक ऋण देता था। मैंने हरि प्रसाद समंथा से बात की। चिट्ठू, मैती, जार लंका एवं अन्य किसी के पास दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं थी। तकनीक अच्छी है। परिष्कृत बीज यूनिवर्सिटी के द्वारा आते थे जो कि धान के लिए स्थानापन्न था। लेकिन वे नगदीफसलों एवं सब्जी से प्रचुर पैसा बनाते थे। ये बीज व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से आने की वजह से महंगे थे। उसी समय एक अच्छी शुरुआत हुई थी- दुग्ध उत्पादन की और उनमें से सभी के पास तीन से पाँच गाये थीं। महिलाएँ इनकी देखभाल करती थी। किसान जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ दलहन महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से आ रही थी। उनकी स्वयं की सरसों (राई) बहुत अच्छी किस्म की थी। जमीन की ढलान नदी से ऊपर थी। दो सौ तीन सौ मीटर के बीच की दूरी मैंने दूसरे गाँव पर ध्यान दिया। लगभग आधी आबादी गरीब थी। यह दूसरी फसल के साथ एकाधिकार वाली फसल का क्षेत्र था। यह फसल वर्षा पर आधारित थी। पैदावार निम्न थी। कई उत्तर संभावित थे किंतु योजना और सरकार की सहायता के बिना उनमें विविधता उत्पन्न करने की बात एक प्रकार का मज़ाक थी।

उसके लिए ध्यान देने की बात है कि, कृषिगत विविधता का प्रभाव खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ता है। इसके कारण नीति असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसे योजना के द्वारा सावधानी पूर्वक निर्वहण करना चाहिए। आज भी संसाधनों का उपयोग कृषि के अलावा अन्य चीजों में हो रहा है। जिसकी वजह से उत्पादन दर निम्न हो सकती है। जब हम अन्य देशों से इसकी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि, यह दर भारत में अत्यंत अल्प है। यूरोप में यह (700 ग्राम) और USA(850 ग्राम) है। भारत में खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता की स्थिति चिंताजनक है। एक गरीब घरेलू उर्जा का अधिक निष्कासन करता है और उस उर्जा को पाने के लिए पूर्णतः खाद्यान्न पर निर्भर करता है इसीलिए नीति का उद्देश्य खाद्यान्न के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी होना चाहिए।

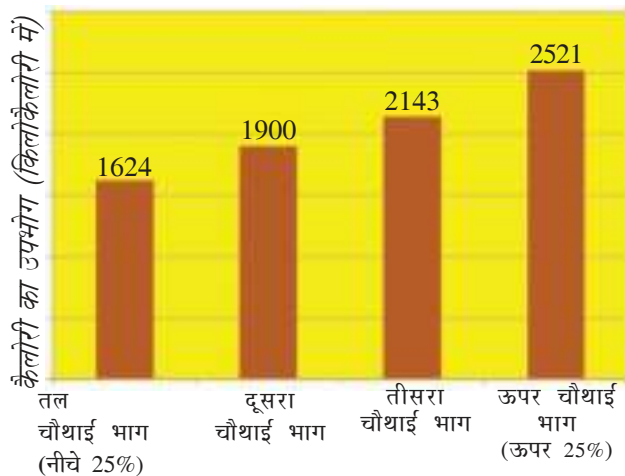
- उन शब्दों और वाक्यों को रेखांकित कीजिए जो हमें कृषिगत विभिन्नता के बारे में बताती हैं और सविस्तार बताइए कि ये भारतीय किसानों के लिए क्यों आवश्यक है।
- अपने-अपने गाँव की या जिस गाँव के बारे में आप जानते हैं उसकी कृषिगत विभिन्नता का वर्णन कीजिए।

## भोजन की सुलभता (Access to Food)

अगला महत्वपूर्ण पहलू खाद्य सुरक्षा का है ताकि, खाद्य-पदार्थ सुलभ हो सके। अन्य पदार्थों एवं खाद्यान्नों का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक को उपभोग के लिए इसे खरीदने में सक्षम होना चाहिए। क्या प्रत्येक व्यक्ति खाद्यान्न की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु समर्थ है?

आप स्मरण कर सकते हैं जो आपने आठवीं कक्षा में पढ़ा है। भोजन जो हम खाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है एवं कैलोरी प्रदान करता है। यह हमारे कार्य करने में सहायक होता है। यदि हम कम से कम पोषक तत्व युक्त भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है जिससे हम कमजोर हो जाते हैं तथा काम नहीं कर पाते हैं। तो यह हमारे स्वास्थ्य एवं

आरेख - 3 : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ली जाने वाली कैलोरी



\* 'व्यय' के विवरण के बारे में, आप आठवीं कक्षा के इसी आरेख से पढ़ चुके हैं।

से कम लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% लोगों के भोजन में आवश्यक कैलोरी की खपत कम है। आरेख 3 में आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोग कैलोरी की न्यूनतम मात्रा ले पाते हैं। वे मानकीकृत 2400 कैलोरी से कम कैलोरी का उपभोग करते हैं। तथापि ये लोग कठिन मेहनत और शारीरिक श्रम करते हैं।

न्यूनतम कैलोरी का सबसे बड़ा कारण है लोगों की क्रय-शक्ति का कम होना। लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है कि, वे खाद्य पदार्थ खरीद सके। यहाँ पर बहुत से कारण हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जन संसाधन आदि। आगे पढ़ने से पहले क्या आप इनमें से कुछ का स्मरण कर सकते हैं?

## जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System (PDS))

राशन की दुकान लोगों की खाद्यान्न आवश्यकता को पूर्ण करने का महत्वपूर्ण जरिया है। 2004-05 में एक सर्वेक्षण किया गया था; यह पता लगाने के लिए कि भिन्न-भिन्न राज्यों के लोग जन वितरण प्रणाली की उचितदरों की दुकानों से क्या खाद्यान्न प्राप्त करते हैं और कुल खाद्यान्न उपभोग में उनका हिस्सा कितना है? आरेख 4 में देखिए। यह भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों की खाद्यान्न पर निर्भरता को दर्शाता है।

- कक्षा आठवीं में की गयी जन-वितरण प्रणाली की चर्चा का पुनःस्मरण कीजिए। देश की खाद्य सुरक्षा से जन वितरण प्रणाली किस प्रकार संबंधित है?

अध्ययन यह बताता है कि, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली का अच्छा रिकार्ड रहा है। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ वैश्विक PDS(जनवितरण प्रणाली) को अपनाया नहीं जाता है, अर्थात् सभी के पास न्यून दर पर खाद्यान्न उपलब्ध है। यह विरोधाभास अन्य राज्यों में है जहाँ निर्धन परिवार रहते हैं वहाँ खाद्यान्न अलग दामों पर बेचा जाता है। गरीबों के लिए अलग और अमीरों लोगों के लिए अलग। यहाँ तक कि, निर्धन, अति निर्धन को अन्य हक दिए

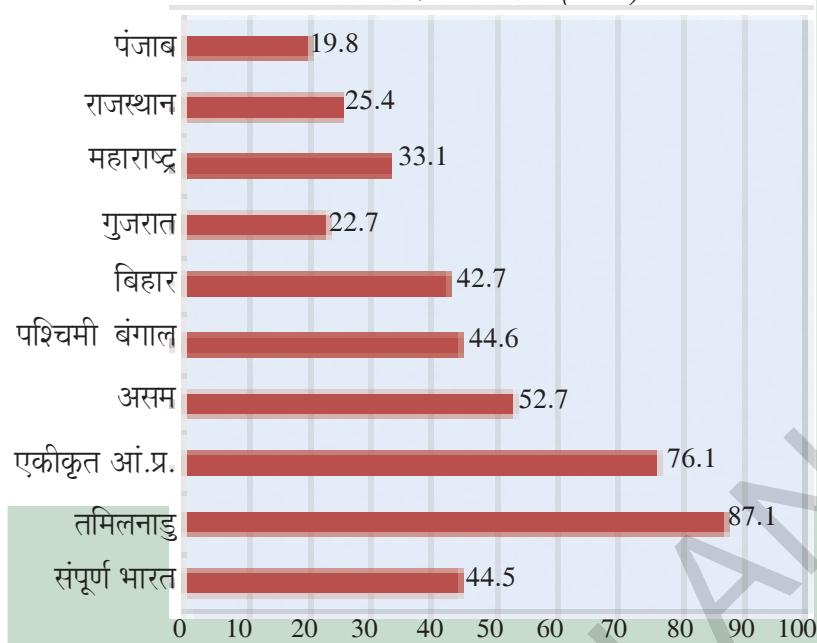
कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रत्येक दिन भोजन में आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवश्यकता से कम है। 1983 और 2004 के बीच में कैलोरी की खपत निम्न है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है।

वितरण की असमानता छिपाया जाना सामान्य नहीं है। बहुत समृद्ध लोग जो खाना खाते हैं वह आवश्यक कैलोरी से ज्यादा पोषक होता है। आबादी का बहुत बड़ा भाग आवश्यक कैलोरी

जाते हैं या सुलभता को सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अंत्योदय कार्डधारक के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) प्रत्येक परिवार के लिए प्रत्येक माह सुनिश्चित है।

आरेख 4 : 2011-12 में चावल एवं गेहूँ का क्रय (प्रतिशत में)  
जनवितरण प्रणाली (PDS)



#### ● रिक्त स्थान भरिए।

संपूर्ण भारत में ..... प्रतिशत लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है लगभग ..... प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित होना है। 2011-12 में, राज्यों में से कुछ राज्यों जैसे ....., ....., ..... में कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से केवल एक चौथाई या उससे भी कम प्रतिशत ने, जन वितरण प्रणाली का उपयोग किया था? ऐसा क्यों होता है? कक्षा में चर्चा कीजिए।

### जन वितरण प्रणाली और बफ़र संग्रह (PDS and Buffer Stock)

खाद्यान्न के भंडार की देखरेख एवं सुरक्षा मुख्यतः FCI (भारत खाद्यान्न निगम) के द्वारा की जाती है। जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। FCI गेहूँ और चावल उन राज्यों के किसानों से खरीदती हैं जहाँ इनका उत्पादन प्रचुर होता है। किसान को पूर्व घोषित कीमत इन फसलों के बदले चुकाई जाती है। इसे न्यूनतम समर्थन कीमत कहा जाता है। MSP प्रत्येक वर्ष 'गवर्नमेंट एजेंसी' द्वारा घोषित किया जाता है।

राज्य एवं केंद्र सरकार खाद्यान्न का एक तिहाई भाग किसानों से लेते हैं। वर्तमान स्थिति में यह खाद्यान्न लोगों में विभिन्न यांत्रिकियों द्वारा बाँटे जाते हैं। इस समय सरकारी एजेंसियाँ जन वितरण प्रणाली के आवश्यक खाद्यान्न की अपेक्षा और अधिक खाद्यान्न हासिल कर रही हैं। अगर सरकारी स्टॉक में प्रत्येक एक वर्ष के बाद वृद्धि होती है तो उपलब्धता कम होती है। (देखिए 2011 के सारणी में खाद्यान्न की उपलब्धता) सरकार की आलोचना होती है कि, जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न नहीं पहुँच पाता है। कभी-कभी सरकार इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करती है। क्या आप सोचते हैं कि खाद्यान्न का निर्यात जो एक मामूली रकम देता है, अच्छा है? जबकि देश की आबादी का बड़ा भाग प्रचुर खाद्यान्न प्राप्ति में सक्षम नहीं है।

2013 में भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कहा गया। कानूनी तौर पर यह लोगों के लिए 'खाद्य का अधिकार' है। यह भारत के दो चौथाई लोगों पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार न्यूनतम आय वाला प्रत्येक परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक महीने सब्सिडी दर पर पाने का अधिकारी होगा।

इस तरह के परिवारों में अति निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न देना सुनिश्चित किया गया। कुछ वर्षों तक केन्द्र सरकार चावल गेहूँ ज्वार बाजरा की आपूर्ति क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये में करेगी। इस नियम-कानून के अनुसार-75% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और 50% शहरी आबादी को अधिकार के है वे जन वितरण प्रणाली से खाद्यान्न खरीदें। अगर सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होगी तो खाद्यान्न खरीदने के लिए नगद राशि दी जायेगी। यह कानून यह भी ध्यान रखता है कि, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली महिलाओं को और 1 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनवाड़ी में आते हैं उनके लिए पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाय।

भारतीय संसद विभिन्न प्रकार के कानून जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित कर रही है- जैसे एकीकृत बाल विकास योजना' (ICDS)। जहाँ भारतीय संसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे अधिनियम और एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाएँ लागू कर रही हैं, वहीं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका भी पूर्व सक्रिय हो रही है। पर गैर सरकारी संस्थानों द्वारा याचिकाकृत कोर्ट केसों पर न्यायिक निर्णयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि पाठशालाओं में पढ़नेवाले सभी छोटे बच्चों को माध्याह्न भोजन उपलब्ध करवायें। पहले यह योजना लघु पैमाने पर तमिलनाडु में प्रचलित थी किंतु इसे अब सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। आज पाठशालाओं में लगभग 14 करोड़ बच्चों माध्याह्न भोजन खाते हैं। जब राज्य सरकार इसे लागू करने से इंकार कर देते हैं तो न्यायालय विभिन्न याचिकाओं और सुझावों द्वारा उन्हें लागू करने का आदेश देता है। जैसे :- माध्याह्न भोजन गर्म-गर्म स्थानीय तौर पर पकाकर दिया जाय (यह अनाज या शुष्क नाश्ते के रूप में न हो) जिसकी आपूर्ति पहले सरकार द्वारा की जाती थी। यह साफ-सुथरा और पोषक (निर्धारित निम्नतम कैलोरी स्तर) हो और सप्ताह के हर दिन अलग-अलग भोजन पदार्थ हो। रसोइये के रूप में दलित, विधवा और लाचार स्त्री को प्रधानता दी जायेगी। यह विश्व की सबसे बड़ा 'विद्यालयी भोजन कार्यक्रम है'। इस योजना के लिए आवश्यक राजस्व की प्राप्ति, सरकार के आदेशानुसार विभिन्न करों द्वारा की जाती है। अब आंगनवाड़ी के बच्चों को भी गर्म, पका हुआ भोजन उपलब्ध हो रहा है।

### पोषण स्थिति (Nutrition status)

अंत में, भोजन की वास्तविक पर्याप्तता को देखने के लिए हम बच्चों और व्यक्तियों की पोषण स्थिति को देखेंगे। इससे हमें उपर्युक्त चर्चित व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ इन क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी पता चलता है। शरीर के लिए प्रत्येक स्तर पर - उर्जा के लिए, शारीरिक अभिवृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए एवं बीमारियों से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस भोजन का हम उपभोग करते हैं उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

**कार्बोहाइड्रेट्स :** यह उर्जा प्रदान करता है जो गेहूँ, चावल, रागी, ज्वार, खाद्य तेल, चीनी, वसा आदि से मिलता है।

**प्रोटीन :** यह शारीरिक - मानसिक वृद्धि में सहायक होता है एवं उत्तकों आदि को सक्रिय करता है। यह हमें बीन्स, दाल, मीट, अंडा, चावल, गेहूँ आदि से मिलता है।

**विटामिन्स :** यह शरीर को सुरक्षा देता है और कई प्रकार के शारीरिक कार्य प्रणालियों को स्वस्थ बनाता है। यह हमें फल, पत्तेदार सब्जी, अंकुरित बीजों, मोटे चावल आदि से मिलता है।

**खनिज :** इसकी आवश्यकता अल्प मात्रा में शरीर की विभिन्न क्रिया कलापों के लिए होती है। जैसे- रक्त के निर्माण के लिए लौह। यह हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, रागी आदि से प्राप्त होता है।

अगर हम एक सर्वेक्षण करते हैं जैसा कि, हमने पूर्व के अध्यायों में किया है। लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं, उसके बारे में उनसे पूछकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ऊपर वर्णित खाद्य समूहों के बारे में मोटा अनुमान लगा सकते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज आदि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। ऐसे में इन सबकी सही मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। पोषण विज्ञानी, कद, वजन आदि के आधार पर बताते हैं कि व्यक्ति पूर्णपोषित है या नहीं।

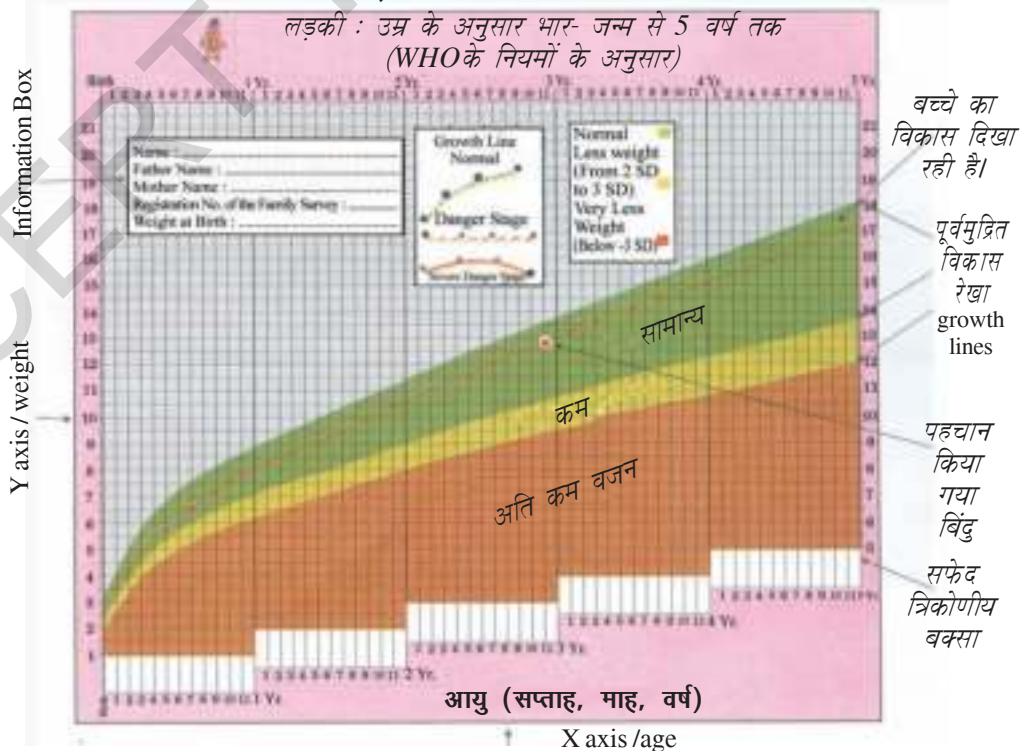
इतनी बड़ी आबादी के लिए पोषण विज्ञानी विभिन्न माप-तोलों और सांख्यिकी ज्ञान का उपयोग कर मानक सीमा निर्धारित करते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर तुलना संभव है। यह हमें लोगों के पोषण स्तर की वैध सूचना देता है।

‘राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद’ द्वारा एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया। यह जानने के लिए कि देश के विभिन्न राज्यों में पोषण का स्तर कुल मिलाकर क्या है? पिछली कक्षाओं में हमने केस अध्ययन किये हैं जिससे हमें निम्न पोषण और निर्धनता से ग्रस्त परिवारों के बारे में पता चला है, किंतु अब इसकी अदृश्य सांख्यिकी के बारे में जानना जरूरी है। ये हमें इस बात को जानने में सहायता करते हैं कि ये स्थितियाँ अपेक्षाएँ हैं या सामान्य मुद्दे हैं। ये हमें अदृश्य और उन मुद्दों को भी जानने में सहायता करती है जिनके बारे में सभी नहीं जानते हैं।

उपर्युक्त विचार के अनुसार पोषण के स्तर का निर्धारण सामान्यतः सही कद, वजन आदि के परीक्षण के लिए किया जाता है। आप कभी आंगनवाडी में जाकर देखें कि, वे किस तरह इसे करते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र होता है। इस उम्र में उनके वजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो एक वयस्क में नहीं होता है।

इसके लिए वजन का मापन सही होना चाहिए और उम्र भी सही होनी चाहिए। इस जानकारी को पोषक विज्ञानियों द्वारा बनायी गई तालिका में दर्ज किया जाता है। वे देखते हैं कि बच्चे सामान्य श्रेणी में हैं या उससे नीचे हैं। यदि हम एक बच्चे का वजन उसकी उम्र के आगे दर्ज करते हैं तो उसे देखकर हमें पता चल जाता है कि बच्चे का भार कम है।

आरेख- 5 आंध्र प्रदेश के आंगनवाडी केंद्र में बच्चों के वजन का माप लेने के लिए उपयोग किया गया चार्ट



NIN का सर्वेक्षण क्या संकेत करता है? 1-5 वर्ष के सात हजार बच्चों का परीक्षण किया गया। देश के बहुत से राज्यों में 45% बच्चे कम वजन के थे। उनका वजन अपेक्षित मानक वजन से भी कम था। वे बच्चे भूखे थे और पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे थे। वे बहुत कम वजन के थे यह आसानी से दृष्टिगोचर हो रहा था। अगर हम सामान्य तौर पर इसे देखें तो हम यह जानने में असमर्थ होंगे कि इस देश में बहुतायत संख्या में बच्चे कम वजन के हैं। इन बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि, वे सामान्य हैं। क्योंकि हमें इन्हें ऐसे ही देखने की आदत हो गई है। सर्वेक्षण हमारी सामान्य सोच को झटका देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि, यह स्थिति गंभीर रूप से देश के आधे बच्चों की शारीरिक मानसिक अभिवृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

रिपोर्ट कहती है -

“कुल मिलाकर कम वजन का दर 45% था। यह 1-3 साल के बच्चों की तुलना में 3-5 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा था। यह प्रचलन 50% से अधिक गुजरात (58%), मध्यप्रदेश (56.9%) और उत्तर प्रदेश में (53.2%) था एवं केरल में सबसे न्यूनतम (24%) था।” गंभीर रूप से कम वजन की समस्या 16% थी।

- मुहल्ले में एक प्रभावकारी अंगनवाड़ी केंद्र इस स्थिति का सामना किस प्रकार करता है? चर्चा कीजिए।

पोषण विज्ञानी तीन भिन्न-भिन्न सारणियों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में इसकी तुलना करते हैं। यह नीचे दिया गया है। ये तीन भिन्नताएँ हमारे सामने उन बच्चों के पोषण के स्तरों की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

| संकेतक                            | सामान्य दर से कम बच्चों के लिए यह क्या दर्शाता है। | अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए                                                                                                                             | देश में बच्चों का प्रतिशत % |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| उम्र के संबंध में वजन का अंकन     | कम वजन                                             |                                                                                                                                                            | 45%                         |
| कद का अंकन उम्र के परिपेक्ष्य में | वृद्धि में रुकावट                                  | जब बच्चे बहुत समय से कुपोषण से ग्रस्त होते हैं तो उनकी हड्डियों का विकास प्रभावित होता है। ऐसे बच्चों का कद अपनी उम्र से कम होगा। इसे छिपाना बहुत कठिन है। | 41%                         |
| वजन का अंकन कद के परिपेक्ष्य में  | कमजोर                                              | जिन्होंने फिलहाल अपना वजन कम किया है उन्हें अगर पर्याप्त आहार दिया जाए तो वह शीघ्रता से सामान्य हो जायेंगे।                                                | 21%                         |

- इस सांख्यिकी का आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस पर एक अनुच्छेद लिखें।

पोषण का स्तर वयस्क पुरुष और स्त्री में “बॉडी मास इंडेक्स” (BMI) के द्वारा मापा जाता है। आपने इसके बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। [BMI=(वजन किलोग्राम में, कद वर्गमीटर में)]। इस अनुक्रमणिका द्वारा तुलना करके किसी व्यक्ति के बारे में (जैसे:- कम वजन दर, सामान्य वजन या अधिक वजन) बताया जा सकता है। इसके अधिक मात्रा में होने से अधिक चर्बी का तथा कम मात्रा से आवश्यकता से कम चर्बी होने का पता चलता है।

‘NIN’ के रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति वयस्क पुरुष और स्त्री में निम्न प्रकार से है। बहुत लंबे समय से भयावह उर्जा की कमी(BMI<18.5) जो पुरुष में लगभग 35% जब कि वजन की अधिकता(BMI>25) 10% थी.....

35% वयस्क स्त्रियाँ लंबे समय से उर्जा की कमी से ग्रस्त थीं और 14% वजन अधिक होने से मोटी थीं। दीर्घकालिक उर्जा की कमी वाले राज्यों में उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। इसके पश्चात 33-38% कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं।

यह किस तरह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है? एक डॉक्टर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में एक समुदाय स्वास्थ्य योजना के तहत काम कर रहा है। जहाँ कम वजन के मरीजों की संख्या बहुतायत में थी। प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या का संबंध उस अध्ययन से था, जिसमें पाया गया कि PDS अनाज 35% कि०ग्रा० प्रत्येक महीना एक परिवार के लिए दिया जाता है, वह केवल 11 दिनों तक ही चलता है। महीने के अंत में वे बाजार अथवा स्वयं के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं।



Fig 10.2 : PDS दुकान

उदाहरण के लिए एक रिक्शाचालक विलासपुर में 70-80 रुपये पाता है। 400 रुपये किराये और 100 रुपये बिजली के देने के बाद वह PDS अनाज पर ही गुजारा करता है। ऐसे

में यह आश्चर्यजनक नहीं था कि, उसने अपना वजन खो दिया और क्षय रोग का शिकार होगया था। ये पैमाने खाद्य सुरक्षा को संकेतित करते हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ने कहा -

“किसी का वजन, और कद कम नहीं होगा अगर वह पर्याप्त आहार लेता है। तंदुरुस्ती का साक्ष्य उसके आहार में है। लंबाई और वजन के पैमाने के द्वारा हम PDS के प्रभाव को, उगाई जानेवाली फसलों के महत्व को, लोगों की क्रय-शक्ति को समझ सकते हैं। इसके साथ ही किसी व्यक्ति का कद यह बता देता है कि उसके बचपन में उसे पर्याप्त एवं सही आहार मिला था या नहीं। कुपोषित और छोटे कद वाले लोगों को देखकर यह समझा जाता है कि ये लोग कुपोषण के शिकार है लेकिन मेरे हिसाब से सही नाम ‘भूख’ होगा।

## निष्कर्ष (Summing up)

पहले अनुभाग का परीक्षण ‘खाद्य सुरक्षा’ मुद्दे के लिए देश में भोजन के कुल उत्पादन के दृष्टिकोण से किया गया। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आगे हम विचार करेंगे कि, किस तरह इस ‘उपलब्धता’ को मापा जाए। यह एक दुखद् तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़नी चाहिए थी वहीं कुछ वर्षों में यह कम हुई है। जो कुछ भी उत्पादित होता है उसे जनता तक पहुँचना

होता है। ये सब बाज़ार में उनके द्वारा की गयी या राशन की दुकान में खरीददारी, के जरिए या फिर विद्यालय भोजन के द्वारा उन तक पहुँचता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग ज़रूरत से कम कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं। यह अन्तर गरीबों में सबसे ज्यादा है। हाँलाकि अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जी, मांस, अंडों की तरफ लोगों का नया चलन है फिर भी कैलोरी की अपूर्णता अभी भी चरम सीमा पर है। PDS व्यवस्था वहीं पर कारगर नहीं हो पा रही है जहाँ उसे सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस गंभीर स्थिति का पता पोषण सर्वेक्षणों द्वारा किये गये सर्वेक्षण से चलता है जो यह दिखाता है कि बच्चों और वयस्कों में एक लंबे समय से ‘कम वजन’ की समस्या चली आ रही है। बहुत समय से 35% से 45% तक लोग उनकी आवश्यकता से कम भोजन कर रहे हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषित (अथवा भूखा) है यहाँ तक कि, जब देश में पर्याप्त खाद्यान्न है। यह स्वीकार्य नहीं है। उपर्युक्त दिशा निर्देश के आधार पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सावधानी से सोचने की आवश्यकता है।

### मुख्य शब्द

|           |          |                              |          |
|-----------|----------|------------------------------|----------|
| उत्पादन   | उपलब्धता | सुलभ                         | पोषकाहार |
| बफर स्टॉक | भूख      | जन वितरण व्यवस्था (पी.डी.एस) |          |

### अपनी सीखने की क्षमता सुधारें

1. मान लीजिए किसी एक वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। किन तरीकों द्वारा उस वर्ष में सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकती है?
2. आपके संदर्भ में खाद्यान्न की सुलभता और कम वजन के बीच के संबंध का वर्णन एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा कीजिए।
3. आपके परिवार के आहार की आदत को साप्ताहिक रूप से विश्लेषित कीजिए। उसमें शामिल पोषक तत्वों की एक तालिका बनाइए।
4. खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न की सुरक्षा के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए।
5. निम्नांकित वक्तव्य के लिए तर्क दीजिए। “जन वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती हैं।”

6. खाद्य सुरक्षा से संबंधित इसी तरह का पोस्टर तैयार कीजिए।



7. पृष्ठ संख्या 137 के अनुच्छेद में “अध्ययन ..... उपलब्ध है। तक अध्ययन कर अपना अभिप्राय व्यक्त कीजिए।
8. भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों की पहचान कीजिए।
- 1) कर्नाटक                      2) ओडीशा      3) गुजरात      4) महाराष्ट्र      5) मध्यप्रदेश  
6) पश्चिम बंगाल              7) छत्तीसगढ़      8) तेलंगाणा      9) उत्तर प्रदेश      10) पंजाब

### परियोजना कार्य

1. निम्नलिखित कविता ‘आई’ पढ़िए। क्या आप खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई कविता लिख सकते हैं। कविता के लिए चित्र बनाइए। अपने बड़ों से भोजन की कमी के बारे में पूछिए और उनके अनुभवों का संकलन कीजिए।

#### आई (माँ) [Aai (Mother)]

मैंने आपको देखा है  
आँसुओं की लहरों में बहते हुए  
अपने पेट की क्षुधा को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए  
सूखे खण्ठ और होंठों से पीड़ित हो  
झील पर बाँध बनाते हुए .....

मैंने आपको देखा है  
चूल्हे के सामने बैठे हुए  
अपनी हड्डियों को जलाते हुए

मोटी रोटियाँ और कुछ थोड़ा-सा बनाते हुए  
सभी को भरपेट खिलाने के बाद,  
स्वयं आधा पेट खाते हुए  
ताकि सुबह के लिए कुछ शेष बच जाये.....  
मैंने आपको देखा है  
कपड़े धोते हुए और बर्तन साफ़ करते हुए  
भिन्न-भिन्न घरों में,  
दिये जाने वाले बचे भोजन को ठुकराते हुए  
गर्व के साथ.....

2. आप के परिवार में, अड़ोस-पड़ोस के परिवार में महीन अनाज के उपयोग के संदर्भ में समाचार प्राप्त कीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए।

| क्रम संख्या | परिवार के मुखिया का नाम | खाया जाने वाला आहार |          |     | उपयोग किया गया अनाज | अनाज की बढ़ोत्तरी या घटाव के कारण |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|
|             |                         | सबरे                | मध्याह्न | रात |                     |                                   |
|             |                         |                     |          |     |                     |                                   |